भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2364

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

2364. डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री कुलदीप राय शर्माः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में राज्य/स्थान-वार कुल कितने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित तकनीकी संस्थानों को राष्ट्रीय एनआईटी का दर्जा प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है और उक्त लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल के वर्षों में एनआईटी का रैंकिंग और प्लेसमेंट के मामले में कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा एनआईटी की रैंकिंग में सुधार करने तथा एनआईटी के समग्र कार्य प्रदर्शन और देश में एनआईटी के ब्रांड में सुधार के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): वर्तमान में, देश के विभिन्न भागों में 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) कार्यरत हैं। एनआईटी की राज्य/स्थान-वार विवरण संलग्नक पर दिया गया है। भारत सरकार ने मई, 2003 में 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आरईसी) का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और एनआईटी के रूप में उनका नामकरण किया था। इसके पश्चात, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज - पटना (बिहार), सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज - रायपुर (छत्तीसगढ़) और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, अगरतला (त्रिपुरा) को क्रमश: वर्ष 2004, 2005, 2006 में एनआईटी के रूप में प्रोन्नत किया गया था। XIवीं और XIIवीं योजनाओं के दौरान, शेष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में 11 नये एनआईटी स्थापित किए गए हैं। इसके तिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में इंजीनियरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिबपुर (पश्चिम बंगाल) को भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईआईईएसटी) शिबपुर (पश्चिम बंगाल) के रूप में नियंत्राधीन कर लिया गया था। इन 31 एनआईटी और आईआईईएसटी, शिबपुर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं' के रूप में घोषित किया गया था।

(ग): इन संस्थाओं में लगभग 1,05,000 विद्यार्थी विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी श्रमशक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। प्रवेश नीति के अनुसार, 50% सीट उस राज्यों के मूल विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है जहां वह एनआईटी कार्यरत हैं। इस प्रकार, राज्यों के विद्यार्थी को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान प्रदान कर रही शीर्ष संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने का लाभ प्राप्त है।

(घ): एनआईटी ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ) 2019 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, शीर्ष 200 इंजीनियरिंग संस्थाओं में एनआईटी-तिरूचिरापल्ली 10वां, एनआईटी राउरकेला 16वां, एनआईटीके 21वां, एनआईटी वारांगल 26वें स्थान पर और एनआईटी कालीकट ने 28वां स्थान प्राप्त किया है। आईआईईएसटी, शिबपुर का एनआईआरएफ-2019 में 12वां रैंक है। औसतन रूप से, एनआईटी के लगभग 75% विद्यार्थी चार वर्षीय अवर स्नातक कार्यक्रमों को पूरा करने बाद प्लेसमेंट प्राप्त करते हैं।

(ड.) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। सरकार विधायी पहलों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत है।

******